सरपंचों और अफसरों ने मिलकर....

पेज 1 का शेष

आरोप लगाया गया कि उसने मरे हुए लोगों के नाम मस्टररोल पर चढ़ाए। उनका फर्जी जॉब कार्ड बनाया और उनके नाम पर सारे पैसे हड़प लिए। ऐसी ही शिकायत ऊंटका गांव के सरपंच आरिश के खिलाफ की गई है। इसने कई जगह गांव में काम कराने के दावे किए लेकिन मौके पर कोई काम नहीं मिला।

हर बैंक में खाते

मनरेगा की ग्रांट के खाते लगभग हर बैंक में खोले जाते हैं। लेकिन मेवात के बेईमान सरपंचों ने बैंकों से कहा कि वे जिन भी लोगों का खाता खुलवाएंगे, उन्हें खोलना पड़ेगा। उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। मात्र सरपंच के अनुमोदन के आधार पर ऐसे खाते खोलने होंगे। सरकारी ही नहीं प्राइवेट बैंकों ने भी मेवात के सरपंचों की बात मान ली और उन्होंने धड़ाधड़ मरे हुए लोगों के खाते भी खोल दिए। सरपंचों ने वहां से पैसा निकालकर या तो अपने खाते में रख लिया या फिर उन्हें कैश लेकर बांट दिया। ये खाते – सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, जिला केंद्रीय कोआपरेटिव बैंक, कोटक महेन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंकों में खोले गए। बैंक को भारी संख्या में खाते और पैसे का ट्रांजैक्शन चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने मेवात में जमकर खाते खोले।

पैसा कैसे आता है और बंटता है

भारत सरकार से यह पैसा राज्य तक आने में किसी भी तरह के घोटाले का शिकार नहीं होता। जब यह पैसा ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव से आगे पंचायत विभाग के वित्तीय सचिव को मिलता है। वहां से इसकी बंदरबांट शुरू होती है। कुल ग्रांट का दो फीसदी चंडीगढ़ में ही ले लिया जाता है, अन्यथा ग्रांट आगे भेजने में दिक्कत खड़ी हो जाती है। वहां से डायरेक्टर पंचायत विभाग, वहां से जिले के डीसी, एसडीएम को, वहां से जिला प्रोग्राम कोआर्डिनेटर को, वहां से जिला परिषद के सीईओ को, फिर बीडीओ, बीडीपीओ, एबीपीओ, पंचायत सचिव, जेई और सरपंच के जरिए अंत में मनरेगा की मजदूरी करने वाले मजदूर को मिलना चाहिए। लेकिन सरपंच के बाद यह पैसा मजदूर तक नहीं पहुंचता। अगर कहीं पहुंचता है तो वह बहुत मामूली और उसमें भी बिना कमीशन दिए पैसा नहीं मिलता। जहां कहीं भी ईमानदारी से मनरेगा में काम हुआ, उन गांवों में बदलाव भी आया है। लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। हरियाणा में मेवात की परिस्थितियों की वजह से सारा पैसा हड़प लिया जाता है।

इतनी लंबी चेन के बावजूद मनरेगा का सबसे ज्यादा पैसा डीसी, एसडीएम, डीपीओ, बीडीओ, एबीपीओ, पंचायत सचिव, जेई और सरपंच खाते हैं। यानी अगर जांच एजेंसियां सिर्फ इन पर नजर रखे तो मनरेगा की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हो सकता है। डीसी के सारी फाइलों पर महज साइन होते हैं लेकिन उसी साइन के बदले डीसी को दो फीसदी पैसा पहुंच जाता है। फरीदाबाद में कथित तौर पर ईमानदार कहलाने वाले कई पूर्व जिला उपायुक्तों तक मनरेगा का दो फीसदी पैसा पहुंचता रहा है।

सबसे ज्यादा घोटालेबाज सरपंच

रुबिया गांव दोहा, शाहिद गांव नंगला, शाकिर खान गांव नीमखेड़ा, संजय कुमार गांव दुधौली कलां, निदा आजाद गांव डुंगरान शहजादपुर, जय सिंह गांव हींगनपुर, परवीन गांव खेड़ी कलां, सगीर अहमद गांव रनियाला पातकपुर, रूमशीदा खान गांव बिसरू, अंजुम गांव बिछोर, संजीदा गांव हाजीपुर, अनीसा गांव इंदाना, शब्बीर अहमद गांव लफूरी, भावर सिंह गांव नई, अकबर गांव थेक, संजीदा गांव जेहटाना, सुरेन्द्र गांव शिकरावा, अरजीना गांव ख्वाजलीकलां, मोहम्मद शरफुद्दीन गांव हसनपुर, नाजिर गांव मोहलाका, जुबैर अहमद गांव नांगल मुबारिकपुर, आमिर खान गांव रानिका, शाइस्ता गांव उमरा, मोहम्मद आरिश गांव उन्तका, फकरुद्दीन गांव टैन, अब्दुल जब्बार गांव बेरी तावडू, नाजरीन गांव धुलावट, हसन मोहम्मद गांव मलहाका। इस सूची में जहां कहीं भी महिला सरपंचों के नाम आए हैं, दरअसल सरपंची की भूमिका में उनके पति, भाई या पिता होते हैं। महिला सरपंच बेचारी घूंघट की आड़ में बस साइन कर देती है।

कौन हैं ये युवक

मुस्लिम बहुल मेवात को हरियाणा सरकार ने सबसे पिछड़ा जिला बना रखा है। किसी भी पार्टी की सरकार आए, मेवात की तरक्की से उसे कोई लेनादेना नहीं है। लेकिन सरकारी स्कीमों के पैसों को हड़पने की यह मुलायम चरागाह है। ज्यादातर आबादी अनपढ़ है। उन्हें न स्कीमों की जानकारी होती है और न ही ग्रांट की। नतीजा यह निकलता है कि सारा सरकारी पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। किसी को उसकी हवा तक नहीं लगती। हाल ही में यहां के कुछ पढ़े-लिखे युवकों ने जनहित कमेटी बनाकर ऐसी स्कीमों और मेवात को मिले पैसे की जानकारी जुटानी शुरू की। इसमें कुछ जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उसी कमेटी के सदस्यों ने मनरेगा के इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। जनहित कमेटी के अध्यक्ष एजाज अहमद, उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्बास, महासचिव वसमुल्ला के अलावा जाकिर हुसैन, आकिब हुसैन, एहसान ने इस जनहित याचिका के सबूतों को जुटाने में अहम भूमिका निभाई। इन्हें हाई कोर्ट में इम्तियाज हुसैन एडवोकेट का साथ मिला। वकील इम्तियाज हुसैन की तारीफ पूरी जनहित कमेटी ने की है, जिन्होंने केस दायर करने का एक भी पैसा नहीं लिया। इम्तियाज भी मेवात के खेड़ला गांव के रहने वाले हैं।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794
6. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
7. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

भारत छोड़ो दिवस पर सीटू की सरकार की नीतियों के खिलाफ हुंकार

भाजपा सरकार को बताया-आजादी के बाद से अब तक की सबसे खराब सरकार

करनाल, (जेके शर्मा) भाजपा सरकार पूंजीपतियों की गोद में खेलना बंद करे। देश के असली निर्माताओं किसान व मजदूर की रोजी रोटी पर हमले बंद करे। सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह न करे। सीटू के प्रदेश महासचिव जय भगवान, खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगमाल सिंह भारत छोड़ो दिवस आंदोलन के ऐतिहासिक दिन पर किसान-मजदूरों के भारत बचाओ सभा व प्रदर्शन को सम्बोधित कर रहे थे। सभा में अध्यक्षता सतपाल सैनी, शीशपाल, रामस्वरूप, रणजीत सिंह ने सम्बोधन में कहा कि मौजूदा सरकार आज़ादी के बाद अब तक की सबसे खराब सरकार साबित हुई है। कोरोना की इस महामारी में भी देश और दुनिया के पूंजीपतियों के मुनाफो में 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। भाजपा के राज में इसी डेढ़ साल में भारत में 100 बड़े पूंजीपतियो ने 13 लाख करोड़ रूपये के मुनाफे कमाए है जबकि एक तिहाई लोगो ने अपने रोजगार खोए हैं, दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही है।

बेरोजगारी अपने शीर्ष पर है। देश के सार्वजनिक व सरकारी उपक्रमों को कारपोरेट घरानों को नीलाम किया जा रहा है। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले किसानों को उजाडने के लिए तीन कृषि कानून लाए गए हैं। किसान 8 महीने से सडक़ों पर हैं लेकिन भाजपा सरकार अंबानी अडानी के मुनाफों के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार ने मजदूरों बारे चार लेबर कोड पारित कर मजदूरों को पूंजीपतियों और ठेकेदारों का गुलाम बनाने का ही काम किया है।

उन्होंने कहा कि बिजली बिल 2021 को पारित करवाकर बिजली को निजी हाथो में देकर जनता पर बिलों के भारी बोझ लाद रही है। इसलिए देश के किसान व मजदूर भारत व देश बचाने के लिए सडक़ों पर उतरे हैं। सीटू जिला प्रधान सतपाल सैनी, सचिव जगपाल राणा, खेत मजदूर यूनियन के जिला प्रधान शिशपाल, किसान सभा के संयोजक कुलदीप एडवोकेट, आंगनवाड़ी यूनियन की नेता रूपा राणा, बिनजेश, आशा यूनियन नेता सुदेश, रोशनी, मिड डे मिल यूनियन नेता शिमला, संतोष, ग्रामीण चौकीदार सभा के कली राम, परवारा राम, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जोगेंद्र सिंह, जनवादी महिला समिति की जरासो देवी, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह, केंद्रीय कमेटी नेता कृष्ण शर्मा, ओ पी माटा आदि ने संबोधित किया। संगठन के नेताओं ने कहा कि न तो स्कीम वर्कर्स व कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा और न ही न्यूनतम वेतन 24000 किया जा रहा। सरकार व विभागों द्वारा स्वीकृत मांगो को ही लागू नही किया जा रहा। सरकार आम जनता की रोज़ी रोटी पर हमले कर रही है जबकि देश की धन संपदा को कोडियो के भाव बेच रही है जिसे देश का किसान मजदूर स्वीकार नहीं करेगा। 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर शहर में जुलूस निकाला गया और नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली कर्मचारियों की 10 अगस्त को होने वाली हड़ताल के समर्थन में प्रस्ताव पारित करके इसमें शामिल होने का फैसला किया।

इस मौके पर मांग की गई कि खेती विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो। फसल की सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी हो। मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड रद्द हों, न्यूनतम वेतन 24000 रूपये हो। वेतन कटौती व छंटनी बंद हो। बिजली बिल-2021 रद्द हो। सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र का नीजिकरण बंद हो। क्रूर आवश्यक प्रतिरक्षा सेवा कानून (ईडीएसए) को वापस लो। 600 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी के साथ न्यूनतम 200 दिन काम सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा पर बजट बढ़ाया जाए। शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हो। मनरेगा में काम एवं भूगतान के जाति आधारित भेदभावपूर्ण परामर्श प्रस्ताव को वापस लिया जाए। सभी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। महामारी की अवधि तक प्रतिव्यक्ति 10 किलो अनाज व अन्य खाद्य सामान फ्री मिले। 7500 रूपये महीना नगद दिया जाए। सभी निर्माण मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो, श्रमिकों को सभी लाभ व सुविधाएं दो। सरकारी स्वास्थ्य का ढ़ांचा मजबूत हो, इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित करें। कोरोना बिमारी का सभी का टीकाकरण फ्री हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोविड से मृत्यु होने पर मुआवजा सुनिश्चित करें। सरकारी विभागो में स्थाई भर्ती हो। कच्चे, ठेका व आऊटसोर्स पर लगे कर्मचारी स्थाई हों। स्कीम वर्कर्स आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, क्रेच कर्मियों, वन मजदूरों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों आदि को स्थाई किया जाए। आवश्यक वस्तुओं, पैट्रोल-डीजल व गैस की कीमतां की वृद्धि वापस लो।

हरियाणा टैक्स बार ने आयोजित की टैक्स पाठशाला

करनाल, (ममो) हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन, करनाल द्वारा टैक्स की पाठशाला बाय मनोज लाम्बा और भारतवर्ष के टैक्स प्रोफेशनल्स के सहयोग से जीएसटी महायज्ञ बैनर के नीचे जीएसटी ओलंपियाड– 2021 (लर्न, अनलर्न, रीलर्न जीएसटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है), जो 29 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। यह 18 जुलाई को शुरू हुआ था।

इस जीएसटी महायज्ञ द्वारा सारे देश के टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ टैक्स पेयर्स को भी भारत में 2 जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी और उसमें कपछले 4 वर्षों में आए बदलाव के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सभी को इस कानून की अच्छी तरह से पालना करने में मदद मिले।

इस महायज्ञ को साकार रूप देने वाली टीम का हिस्सा रहे अम्बाला टैक्स बार एसोसिएशन के मुख्य समन्वयक संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जीएसटी महागुरु बिमल जैन के द्वारा 'जीएसटी की यात्रा के 4 वर्ष' पूरे होने पर उनके वक्तव्य से हुआ।

संजीव अरोड़ा ने आगे बताया कि यह कार्यक्रम हफ्ते में तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम को होगा और अक्टूबर माह तक चलेगा। इस कार्यक्रम के 45 से ज्यादा सत्र हैं , जिसमें 54 से ज्यादा भारत के प्रख्यात जीएसटी वक्ता अपने कार्यों पर अपनी जानकारी व ज्ञान को सभी प्रतिभागियों के साथ साझा करेंगे।

फार्म हाउसों पर चल रही है जेसीबी....

पेज एक का शेष

खोरी के लोग मायूस

खोरी बस्ती में अपना सब कुछ गवां चुके लोग अब चाहते हैं कि वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध फार्म हाउसों को हटाया जाए। खोरी के रहने वाले जमील का कहना है कि हम लोगों को जिस तरह उजाड़ने की जल्दबाजी एमसीएफ को थी, अब वही रवैया फार्म हाउसों के लिए क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस, एमसीएफ और अदालत का रवैया खोरी के गरीबों के लिए कुछ और था और अब फार्म हाउसों के लिए अलग है। जमील ने सवाल किया कि कांत एन्क्लेव के निवासियों ने भी तो तमाम दस्तावेज पेश किए थे लेकिन इसके बावजूद कांत एन्क्लेव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया। आखिर फार्म हाउसों के मामले में अदालत क्यों नहीं उन्हें गिराने की समय सीमा तय कर रहा है। जमील ने कहा कि अगर एक दिन में 30-40 फार्म हाउस अगर गिरा दिए जाएं तो हम खोरी वालों को कुछ तो चैन मिल जाएगा।

कर्ज कैसे चुकाएंगे शिक्षण संस्थान

अरावली जोन में स्थित मानव रचना यूनिवर्सिटी, अरावली इंटरनैशनल स्कूल, एमवीएम पब्लिक स्कूल समेत कई अन्य शिक्षण संस्थाओं, बैंक्वेट हॉल मालिकों ने तमाम बैंकों से मोटा कर्ज ले रखा है। ऐसे में मानव रचना और बाकी संस्थान इन कर्जों को कैसे चुकाएंगे। टूटने पर दो स्थितियां बनेंगी। टूटने के बाद वो जमीन वन विभाग को चली जाएगी। जबकि बैंकों के पास यह जमीन और बिल्डिंग गिरवी है। क्या बैंक अपना पैसा खो बैठेंगे या फिर उन संस्थाओं को उजड़ने की हालत में भी बैंकों से लिया कर्ज लौटाना होगा। बहुत मुमकिन है कि मानव रचना और शिक्षण संस्थाओं के मालिकान अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएं और इसकी आड़ में भी और मोहलत मांगें।

अभी तक सलाहकार क्यों

हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो एफएमडीए (फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण) बनाया है, उसमें 6 गैरसरकारी सदस्य रखे गए हैं। ज्यादातर सदस्यों में प्रॉपर्टी डीलर और उद्योगपति हैं। इन्हीं सलाहकारों में एक नाम है अमित भल्ला का। अमित भल्ला ही मानव रचना यूनिवर्सिटी का मालिक है। ताज्जुब है कि अरावली में मानव रचना जैसा बड़ा संस्थान और एक अन्य फार्म हाउस में सीधा नाम आने के बावजूद न तो इस शख्स ने खुद से इस्तीफा दिया और न ही इससे भाजपा या सरकार ने इस्तीफा मांगा। नियमानुसार विवादास्पद होने के बाद एफएमडीए से अमित भल्ला को हटाया जाना चाहिए था लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर मानव रचना को लेकर इतने दबाव में हैं कि वे कैसे साहस कर इस्तीफा मांगें। बता दें कि मानव रचना यूनिवर्सिटी की आड़ में अमित भल्ला ने भाजपा और संघ के नेताओं से सीधे दोस्ती गांठ रखी है। अभी हाल ही में विश्व हिन्दू परिषद की राष्ट्रीय बैठक मानव रचना में हुई थी, जिसका खर्च अमित भल्ला ने ही उठाया था। ऐसे में हरियाणा सरकार मानव रचना को बचाने में जी जान से जुटी हुई है।